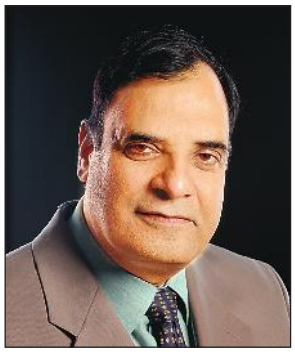

आलोक मेहता

जमीन से कटे शीर्ष नेता एवं प्रचार प्रबंधक

कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार और पार्टी के प्रचार प्रबंधकों ने इन दिनों अरबों रुपयों के विज्ञापन जारी किए हैं। अखबार, टी.वी., रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि में चमकते आंकड़े और चमकते चेहरे। ऐसा ही एक विज्ञापन 'भारत निर्माण के प्रमाण' श्रृंखला का है- ''पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़कों का निर्माण और उनके स्तर में सुधार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2 लाख 67 हजार किलोमीटर के ग्रामीण सड़क नेटवर्क का काम और ग्रामीण क्षेत्र से अनाज, सब्जी, फल-फूल को मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों को 33 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की सुविधा।'' इन आंकड़ों से अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बड़े-बड़े नेता एवं कारपोरेट कंपनियों के प्रबंधक अवश्य चमत्कृत हो सकते हैं। लेकिन याद कीजिए मात्र 100 दिन पहले हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शीर्ष नेता भाजपा शासित राज्यों में आक्रोश के साथ कह रहे थे- 'सड़कें इन राज्यों के विकास का प्रतीक नहीं हो सकतीं। हमें तो गरीबों और पिछड़ों को आगे बढ़ाना है।' संभव है उन्होंने स्वयं या उनकी सलाहकार मंडली ने तब या बाद में भी धारणाओं की समीक्षा नहीं की। लेकिन एक जिज्ञासु पत्रकार के नाते हमने असलियत जानने की कोशिश की। यह बात सामने आई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, रमन सिंह, अशोक गहलोत, शीला दीक्षित ने अपने राज्य में विभिन्न शहरों की सड़कें सचमुच बेहतर बना दी। हालांकि, इन राज्यों से जुड़े 'राष्ट्रीय राजमार्गों' के रखरखाव के लिए दस वर्ष पहले राज्य सरकारों को दी जाने वाली जिम्मेदारी तथा बजट राशि केंद्र की 'महान' मनमोहन सरकार ने छीन ली थी। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए बने मंत्रालय की जिम्मेदारियों कभी बदलती रहीं और कभी लालफीताशाही भ्रष्टाचार के दलदल में फाइलों पर सड़कों के आंकड़े बढ़ाती-घटाती रही। इसलिए राहुल गांधी की टीम के प्रमुख नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, सी.पी. जोशी के गृह राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत खस्ता होती गई। सरकार और पार्टी की सफलता के दावे करने वाले शीर्ष नेताओं ने क्या कभी दिल्ली से ग्वालियर-भोपाल या दिल्ली से जयपुर-अजमेर-जोधपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग से सामान्य गति वाली गाड़ियों से यात्रा की है? जवाब होगा- नहीं, क्योंकि उनके पास इतना वक्त कहां था? इसलिए वे पार्टी प्रबंधकों द्वारा जुटाए गए विमानों अथवा हेलीकाप्टर से दौरे करते रहे। तभी तो राज्यों के भाजपा या कांग्रेस के जीते-हारे हुए मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार के मदमस्त नेताओं की अदूरदर्शिता एवं विफलताओं का कच्चा-चिट्ठा सामने रख देते हैं। वही आज सरकारी विज्ञापनों को पढ़ते हुए जब राष्ट्रीय राजमार्गों से यात्रा करते हैं, तो टूटी-फूटी हालत और दुर्घटनाओं को लेकर सरकार का मखौल उड़ाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा या कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों ने सन् 2000 से राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें सरकारी खजाने के अलावा निजी कंपनियों के ठेकेदारों की भागेदारी के साथ बनवाईं और उन्हें 'टोल टैक्स' वसूलने का जिम्मा दे दिया। नतीजा यह है कि दिल्ली-हरियाणा-राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में टोल नाकों पर विरोध-हिंसा होने लगी। ठेकेदार घाटे का रोना रोने लगे तथा सड़कें बदतर होती चली गईं।

सरकार और पार्टी की सफलता के दावे करने वाले शीर्ष नेताओं ने क्या कभी दिल्ली से ग्वालियर-भोपाल या दिल्ली से जयपुर-अजमेर-जोधपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग से सामान्य गति वाली गाड़ियों से यात्रा की है? जवाब होगा- नहीं, क्योंकि उनके पास इतना वक्त कहां था? इसलिए वे पार्टी प्रबंधकों द्वारा जुटाए गए विमानों अथवा हेलीकाप्टर से दौरे करते रहे। तभी तो राज्यों के भाजपा या कांग्रेस के जीते-हारे हुए मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार के मदमस्त नेताओं की अदूरदर्शिता एवं विफलताओं का कच्चा-चिट्ठा सामने रख देते हैं। वही आज सरकारी विज्ञापनों को पढ़ते हुए जब राष्ट्रीय राजमार्गों से यात्रा करते हैं, तो टूटी-फूटी हालत और दुर्घटनाओं को लेकर सरकार का मखौल उड़ाते हैं।

'तरक्की' के हाथ का ऐसा ही दावा अल्पसंख्यक मतदाताओं के लिए जोर-शोर से हो रहा है। सरकार चुनाव से कुछ महीने पहले दावा कर रही है कि अगले तीन-चार वर्षों में मुसलमानों के कल्याण के लिए 10 लाख 12 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री ने ही पिछले दिनों कहा कि राष्टीय वक्फ विकास निगम यह धनराशि जुटाएगा। जनवरी में इसकी प्रारंभिक पूंजी 500 करोड़ रुपये रखी गई। सवाल यह है कि पिछले चार वर्षों के दौरान सरकार ने बड़ी मेहरबानी क्यों नहीं की? हालत यह थी कि मनमोहन सरकार और राहुल गांधी की प्रिय अंग्रेजीदां टीम के बड़े नेता सलमान खुर्शीद जिस समय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री रहे, तो निर्धारित बजट में से भी 400 से 600 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं हुए। नतीजा यह हुआ कि 'काबिल' वित्त मंत्री पलनिअप्पन चिदंबरम ने नए वित्तीय वर्ष में इतनी धनराशि की कटौती कर दी। उनका तर्क रहा है कि 'जब आप इतना भी खर्च ही नहीं कर सकते, तो अधिक रकम से बही-खाता क्यों खराब किया जाए।' बहरहाल, नए मंत्री रहमान खान ने कुछ महीनों में गाड़ी पटरी पर बैठाई तथा कुछ योजनाएं आगे बढ़ाई। लेकिन यहां भी खेल है। मंत्रालय के मौलाना आजाद प्रतिष्ठान से छात्रवृत्तियों के नाम पर तीन-चार सौ करोड़ का बजट दिखाया गया। जब पूछा गया कि छात्रवृत्तियों पर तो इतना खर्च नहीं हुआ, तो जवाब मिला- 'यह राशि तो बैंक में जमा रखने की है और बैंक से मिलने वाले ब्याज की राशि छात्रवृत्तियों के रूप में जाती है। फिर यह काम भी राज्य सरकारों के मार्फत होता है।' मतलब करोड़ों के खजाने को दिखाकर दो-चार हजार रुपयों की दरियादिली से अल्पसंख्यक युवाओं के दिल जीतने की कोशिश। स्व रोजगार के लिए मात्र 50 हजार से एक लाख रुपये की व्यवस्था है। इतनी धनराशि में गरीब क्या मशीन, कल-पुर्जे के साथ दो मजदूरों को एक सौ दिन भी कुछ खिला सकेगा? पराकाष्ठा यह है कि राहुल दरबार के किसी 'मोबाइल' युवा एक्सपर्ट को कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल का प्रमुख बना दिया गया। राहुल गांधी तो बुजुर्ग नेताओं के साथ संस्कारवश शालीन व्यवहार रखते हैं। लेकिन उनकी टीम के लोग केजरीवाल शैली में मंत्रियों से जवाब तलब करते हैं। इंदिरा गांधी युग से पार्टी तथा अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाले शरीफ रहमान खान 'कल के छोकरे' को काम का 'हिसाब-किताब' देते कितना दर्द महसूस करते होंगे?

राहुल टीम के प्रचार तंत्र के प्रबंधकों की माया है कि हर तीसरे दिन पार्टी के किसी नए प्रवक्ता की किसी गलती पर माफी मांगनी पड़ती है। प्रचार प्रबंधकों के पास कंप्यूटर में उपलब्ध आंकड़ों और तथ्यों के अलावा पृष्ठभूमि की कोई जानकारी नहीं होती। नेहरू युग की बात दूर रही, उन्हें इंदिरा युग के शीर्ष नेताओं के विचार ही नहीं नाम तक याद नहीं होते। इसलिए वे रोबोट की तरह बोलते नजर आते हैं। राहुल गांधी केजरीवाल पार्टी की तर्ज पर जनता की नब्ज समझने के लिए प्रदेशों में घूम रहे हैं। सवाल है, मध्य प्रदेश जैसे परंपरावादी प्रदेश और महिला कांग्रेस की प्रतिनिधियों के बीच 'समलैंगिक संबंधों' की आवश्यकता के एजेंडे से क्या कांग्रेस लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच सकती है? मनमोहन सिंह या राहुल गांधी के इरादे कितने ही नेक हों, उनके अधिकांश प्रबंधक पार्टी की नैया तूफानी भंवर में ही फंसाते चले जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि प्रतिपक्ष का हर नेता इस स्थिति और अनाड़ीपन का लाभ उठाने के कोशिश करेगा।

alokmehta7@hotmail.com